country are collected by the Reserve Bank of India (RBI). According to the latest RBI data, 16990 units in the small scale sector and 47 in the Non-Small Scale Sector were sick in the State of Madhya Pradesh as at the end of September 1990.

Major causes of industrial sickness as reported by the banks related to marketing, financial, labour, management and production problems and to external factors like power shortage demand recession and natural calamities.

लघु उद्योगों में इक्विटी निवेश

1294. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े और अन्य औद्योगिक उपक्रमों को लघु उद्योगों में इक्विटी निवेश करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसके कारण लघु उद्योगों के स्वतंत्र अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) (क) और (ख) लघु, अति लघु और ग्रामीण उपक्रमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए संसद में 6-8-1991 को नीति संबंधी उपाय घोषित किये गये थे, इन उपायों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि लघु उद्योगों में इक्विटी धारिता के लिए अन्य औद्योगिक उपक्रमों को भी मंजूरी दे दी जाए, किन्तु उनका अंश कुल अंशधारिता का 24% से अधिक नहीं होने दिया जाएगा । 24% अंशधारिता के बारे में विस्तृत अधिसूचना की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जा रही है और यह अधिसूचना उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संसद के समक्ष रख दी जाएगी ।

(ग) अन्य औद्योगिक उपक्रम की अंशधारित 24 प्रतिशत तक होने से लघु उद्योगों के मूल स्वरूप या उनके व्यक्तिगत अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस प्रकार की अंशधारिता की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग एकक का नियंत्रण अन्य औद्योगिक उपक्रम उपक्रमों के हाथों में न चला जाए । आशा है कि इससे लघु उद्योगों को जोखिम वाली पूंजी अधिक मिलेगी, नयी तकनोलोजी प्राप्त होगी, बिक्री के लिए नये मार्ग प्रशस्त होंगे तथा उच्च तकनीकी मदें मिलने से उन्हें लाभ होगा।

उदारीकृत आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन

1295. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकृत आर्थिक नीतियों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है जिनमें लाइसेंस व परमिट प्रणाली को समाप्त किया जाना शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त ठोस परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में आर्थिक नीतियों में यदि किन्हीं परिवर्तनों का प्रस्ताव है ; तो वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) (क) से (ग) औद्योगिक परिवर्तनों के पूर्ण परिणाम औद्योगिक क्षेत्र में किए जा रहे निवेश के फलीभूत हो जाने के बाद प्राप्त होंगे । तथापि, जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा हो जाने के बाद, उद्यमियों द्वारा औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए 31 जनवरी, 1992 तक औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 3550 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं । उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल 760 विदेशी सहयोग के अनुमोदन भी दिए गए हैं जिनमें विदेशी निवेश

प्रस्तावों के लिए 260 अनुमोदित शामिल हैं जिनमें 588.63 करोड़ रु० की विदेशी/एन०आर०आई० इक्विटी अन्तर्ग्रस्त है । आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना एक अनवरत प्रक्रिया है और जब आवश्यक होता है, ये परिवर्तन किए जाते हैं ।

कानपुर के चमड़ा उद्योग में संकट की स्थिति

1296. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में चमड़ा उद्योग, सहायक फैक्ट्रियों के बंद हो जाने के कारण संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1297 *[Transferred to the 17th March, 1992]*

Recession in two-wheeler industry

1298. SHRI P. UPENDRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a serious recession in the two-wheeler industry; and the production has further dropped during the last quarter of 1991; and

(b) if so, the reasons therefor and what assistance Government propose to provide to the two-wheeler industry to regain its viability?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.J. KURIEN) : (a) There is a decline in the production of two wheelers in the country during the period October-December 1991, as compared to the corresponding period of last year.

(b) This could be attributed to decline in demand resulting from tightening of monetary policy of Government in order to control fixed deficit and increase in prices. Government has since relaxed the import compression measures.

उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना

1299. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान और आठवीं पचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में मझौले और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी धन राशि प्रदान किए जाने की सभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) 8वीं पचवर्षीय योजना अवधि (1992–97) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े, मझौले और लघु उद्योग लगाने के लिए अनुमोदित परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, चालू वर्ष (1991–92) के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना में योजना आयोग ने बड़े तथा मझौले उद्योगों के लिए 6450 लाख रुपये और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 4436 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है ।